LOK SABHA

Thursday, December 15, 1977/Agrahayana 24, 1899 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in The Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Earnings from Public Call Offices

*426. SHRI V.A. SEYID MUHAMMAD: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of public call offices in the country, at present;

(b) the amount Government have collected from these public call offices during the six months preceding April 1, 1977 and the six months following April 1, 1977;

(c) whether such collection is inadequate and gradually decreasing; and

(d) if so, the reasons therefor and the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) No. of long-distance public call offices in the country as on 15-11-77 was about 6900.

(b) The revenue collected from long-distance public call offices during the period October, 1976 to March, 1977 was Rs. 50.47 lakhs and during the period April, 1977 to September, 1977, Rs. 47.53 lakhs

(c) yes, Sir.

(d) In pursuance of the policy for opening more Public Call Offices at block tehsil/sub-tehsil headquarters and other such places on loss, more and more PCOs are being opened on loss. Moreover, the PCOs earning more revenue are being converted into telephone exchanges due to the demand for local telephones. Provision of telephone facility at under-developed areas by long distance P.C.Os. even on loss at certain categories of stations is a deliberate policy of the Department.

DR. V. A. SEYID MUHAMMAD: Will the Minister be pleased to give State-wise and rural area-wise break-up of the figure?

SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI : Andhra Pradesh.

MR. SPEAKER: If you have got this information, you can place it on the Table of the House.

DR. V. A. SEYID MUHAMMAD: Will the Minister be plased to state if the Government would take adequate steps to have more public call offices in the rural areas as well as in the State where there is deficiency for these?

SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI : We are doing it this year.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि यह टेलीफोन का विभाग सरकार का ऐसा विभाग है जो सरकार की गलती पर सरकार को कमाई कर के देता है ? हम टेलीफोन घुमाते हैं और रांग नम्बर मिलता है लेकिन हमारे पचास पैसे उस में चले जाते हैं । तो सरकार की गलती से कमाने वाला यह विभाग जो सरकार का है उसको सरकार कब तक दुरुस्त करेगी और क्या सरकार इस के आंकड़े बताएगी कि सरकार की गलती से इस विभाग ने कितने रुपये कमाए हैं ।

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साव : ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर में कहा है कि सरकार घाटे में इस को चला रही है और कुछ सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की योजना भी सरकार की है। मैं जानना चाहता हूं कि कितना घाटा प्रति वर्ष सरकार को होता है और प्रति वर्ष कितने फोन लगाने का लक्ष्य आप ने रखा है और प्रत्येक गांव में टेलीफोन पहुंच जाय उस में कितना समय लगेगा, और यह जो आप ने 18 पैसे रखा है यह बहुत ज्यादा है, इसे कम करने के लिए कोई व्यवस्था है ?

श्री नरहरि प्रसाद सुख देव साव : इस साल दो हजार पी सी ओ लगाने का लक्ष्य है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैंने पूछा कि आप प्रति वर्ष कितना घाटा उठाते हैं और प्रति वर्ष कितने फोन सार्वजनिक क्षेत्र में लगाना चाहते हैं ? मैंने यह भी पूछा था कि यह जो मूल्य रखा है 18 पैसे क्या सरकार इस को कम करने का इरादा रखती है ?

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : जो आप ने पूछा है घाटे के बारे में, घाटा तो होता है लेकिन घाटे की पूरी फिगर हमारे पास नहीं है। वह आप नोटिस देंगे तो हम बता देंगे।

श्री हुकम चन्द कछवाय : इस का उत्तर नहीं आया कि प्रति वर्ष कितने फोन सार्वजनिक क्षेत्र में लगाने का आप का लक्ष्य है ?

श्री बृज लाल वर्मा : 2 हजार इस साल लगेंगे और 2 हजार अगले साल लगेंगे।

श्री हुकम चन्द कछवाय : : मैं ने 18 पैसे मूल्य को कम करने के बारे में पूछा था और मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि गलत जगह डायल हो जाय तो पैसे वापस आ जायं ऐसी कोई मशीन आप लगाना चाहते हैं ?

MR. SPEAKER: He has not got the material.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: Is the Minister aware that a large percentage of these public call offices remains out of order at any point of time? I would like to know the percentage of such public call offices which really do not function.

MR. SPEAKER: He has no information.

श्री सुरेन्द्र विक्रम : माननीय मंत्री जी ने एक स्कीम ऐसी बनाई थी कि जिन गांवों की आबादी 5 हजार की हो उसे पी सी ओ से जोड़ देंगे, तो क्या उन्होंने सर्वे कराया है कि भारतवर्ष में कितने गांव पांच हजार या उससे अधिक आबादी के हैं और उन्हें कब तक जोड़ने की योजना है ?

MR. SPEAKER: That particular question has been answered sometime back. The same question cannot come again.

श्री बृज लाल वर्मा : दो हजार पापुलेशन के 40 हजार विलेजेज हैं और उसमें 12 हजार में हमने लगा दिया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम : बाकी कब तक लगा देंगे ?

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साव : जल्दी लगा देंगे।

श्री बृज लाल वर्मा : दो हजार के हिसाब से हर साल लगायगें।

श्री सोमजी भाई डामोर : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आवागमन की दृष्टि से जो गांव दूर हैं, जहां पर रेलवे

लाइन और सड़कें नहीं हैं उनको आप प्राथमिकता देंगे ?

श्री ब्रज लाल वर्मा : एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से जो स्थान महत्वपूर्ण हैं जैसे जिला, सदर तहसील, तहसील, ब्लाक और थाने—उन स्थानों को हम प्राथमिकता दे रहे हैं और उसके बाद 5 हजार और ढाई हजार की आबादी वाले गावों को प्राथमिकता देंगे ।

श्री सोमजी भाई डामोर : मंत्री जी ने बताया कि घाटा हो रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई घाटा नहीं है, इसकी वे जांच करा लें । यह कमाने का धंधा है ।

श्री रामधारी शास्त्री : मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि घाटा उठाकर तहसील कार्यालयों में टेलीफोन लगाया जाता है लेकिन यह कहना कहां तक उचित है कि इसकी फिगर्स उनके पास नहीं हैं । जब उन्होंने जवाब दिया है कि घाटा उठा कर टेलीफोन लगाया जाता है तो उनको आंकड़े भी देने चाहिएं कि कितना घाटा होता है और उसको पूरा करने के लिए सरकार क्या कर रही है । मंत्री जी को यह जवाब देना चाहिए । अगर वे जवाब न दें तो आप उनसे यह जवाब दिवायें ।

इसके साथ ही मंत्री जी यह भी बतायें कि ब्लाक और तहसील स्तरों पर टेलीफोन केन्द्र बनाने की जो योजना है उस का लक्ष्य कितने सालों में पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय : पी सी प्रो की रेवेन्यु जब बढ़ती है तब उसको एक्सचेंज में कन्वर्ट कर लेते हैं । पी सी प्रो में रेवेन्यु कम होती है, वह लास में चलते हैं लेकिन जब उनकी रेवेन्यु बढ़ जाती है तब उनकी एक्सचेंज में कन्वर्ट कर लेते हैं ।

श्री रामधारी शास्त्री : मैंने पूछा था कि ब्लाक और तहसील स्तर पर टेलीफोन लगाने का लक्ष्य कब तक पूरा हो जायेगा ।

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय : दो साल में ।

Some hon. Members *rose*—

MR. SPEAKER: No, please.

Next question—Shri Prasannabhai Mehta—not here. Then, Shri Jaffer Sharief—he is also absent.

SHRI K. LAKKAPPA: I would like to submit that under rule 48(3),

"If on a question being called, it is not asked or the member in whose name it stands is absent, the Speaker may, at the request of any member, direct that the answer to it be given."

This is a very important question. I request that since the member is absent you may ask the Minister to answer it.

MR. SPEAKER: Next question. This is your own question.

Intercepting Mail of certain Political Leaders

*429. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry is being blamed that the important mail of certain political leaders is being intercepted still as was done in the Emergency period;

(b) is so, how far this is true;

(c) whether the former Prime Minister had alleged about the same;

(d) what are the main reasons for this; and

(e) whether the officials responsible for intercepting the mail are still in the Ministry and are helping the present Government also in intercepting the mail of opposition leaders and the action being taken against them?